भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 445

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

नक्ष क्षमता निर्माण कार्यक्रम

†445. श्री दिनेशभाई मकवाणाः

श्री लुम्बाराम चौधरीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री जनार्दन मिश्राः

श्री राजकुमार चाहरः

श्रीमती अपराजिता सारंगीः

श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

श्री खगेन मुर्मुः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मई 2025 में संपन्न राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण (नक्ष) क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण की प्रमुख उपलब्धियों और परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार की आगामी चरणों में नक्ष पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्तावित स्थानों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नक्ष पहल किस प्रकार शहरी विकास, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, शहरी विकास, प्रशासनिक आधुनिकीकरण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से बेहतर स्थानीय शासन के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है; और

(ङ) क्या सरकार का खानदेश क्षेत्र में शहरी भूमि प्रशासन और नियोजन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलगाँव में नक्ष प्रशिक्षण या कार्यान्वयन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत, आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके शहरी भूमि का सर्वेक्षण करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए नक्शा कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। क्षमता निर्माण, नक्शा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, और एक संरचित तीन-चरणीय प्रशिक्षण ढांचे की संकल्पना की गई है जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।

हैदराबाद स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईजीएसटी) में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का चरण-1 मई 2025 में संपन्न हुआ जिसमें चार चक्रों में गहन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।ये प्रशिक्षण सत्र, भाग लेने वाले सभी 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व विभागों, शहरी विकास विभागों के अधिकारियों और जीआईएस डोमेन विशेषज्ञों के साथ-साथ पांच नामित उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) नामतः

- यशवंत राव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (वाईएएसएचएडीए), पुणे
- महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए), चंडीगढ़
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी
- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई), मैसूरु
- पूर्वोत्तर भूमि प्रशासन उत्कृष्टता केंद्र (एनईसीओईएलजी), गुवाहाटी, के भू-विशेषज्ञों के लिए लक्षित थे।

नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1. मास्टर ट्रेनर्स के राष्ट्रीय कैडर का सृजन: एनआईजीएसटी, हैदराबाद में चार दौरों के गहन प्रशिक्षण के माध्यम से, 160 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है -जिनमें 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राजस्व और शहरी विकास विभागों के अधिकारी और निर्दिष्ट उत्कृष्टता केंद्रों के जीआईएस विशेषज्ञ शामिल हैं। ये अधिकारी, अब राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर प्रशिक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने में प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे देश भर में ज्ञान का आदान-प्रदान और कार्यान्वयन में एक रूपता सुनिश्चित हो रही है।

2. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का संस्थानीकरण - नक्शा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को शहरी भूमि सर्वेक्षणों के लिए एकसमग्र तकनीकी रूप रेखा के रूप में विकसित किया गया है। यह एसओपी, डेटा संग्रह, भू-स्थानिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और संपत्ति अभिलेखों के एकीकरण संबंधी एक समान दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिससे ग्राउंड ट्रुथिंग और मानचित्रण के लिए एक सुसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

3. एक समग्र प्रशिक्षण पुस्तिका का विकास: फील्ड स्तर पर नक्शा के कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है। यह सर्वेक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए चरण-दर-चरण विस्तृत मार्ग दर्शन प्रदान करती है, जिसमें जीएनएसएस रोवर्स, ईटीएस और वेब-जीआईएस एप्लिकेशन जैसे आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के साथ प्रचालन कार्यों का संरेखन किया गया है। यह पुस्तिका, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फील्ड-स्तरीय सर्वेक्षण टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए एक मुख्य संसाधन के रूप में उपयोग में लाई जा रही है।

(ख) और **(ग)** इस कार्यक्रम के वर्तमान चरण के अंतर्गत कोई योजना नहीं है।

(घ) नक्शा कार्यक्रम, हवाई और स्थलीय सर्वेक्षणों के माध्यम से सटीक भू-स्थानिक डेटा सृजित करके वैज्ञानिक शहरी भूमि अभिलेखों के सृजन को सक्षम बनाता है, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को बेहतर शहरी नियोजन, अवसंरचना विकास, आपदा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण आदि में समर्थ बनाता है। यह भू-खंडकी सीमाओं को अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर), संपत्ति होल्डिंग कर, पंजीकृत विलेख आदि के साथ एकीकृत करके एक डिजिटलीकृत, स्थानिक रूप से संदर्भित शहरी भूमि अभिलेख प्रणाली के सृजन और प्रत्येक संपत्ति को अर्बन प्रॉपर्टी (अरप्रो) कार्ड

प्रदान करने में सहायता करता है। जिससे भू-स्वामित्व की स्पष्टता बढ़ती है और भूमि विवादों में कमी आती है। यह कार्यक्रम ड्रोन, जीएनएसएस/सीओआरएस-आधारित सर्वेक्षण और वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है, जिससे रियल टाइम में डेटा तक पहुंच संभव होती है और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। नागरिकों के लिए भूमि अभिलेखों को आसानी से सुलभ बनाकर नक्शा कार्यक्रम शहरी निवासियों को सशक्त बनाता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और जीवन को सरल बनाने में सहायक है। यह सटीक संपत्ति मानचित्रण और कर मूल्यांकन में सुधार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करता है। कुल मिलाकर, नक्शा कार्यक्रम सरकार की डिजिटल गवर्नेंस, शहरी परिवर्तन और समावेशी, नागरिक-केंद्रित विकास की दृष्टि को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

(ङ) इस कार्यक्रम के वर्तमान चरण के अंतर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है।

******